

**COMMERCIAL
UNIT**



U.P. Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd.
14th floor, Shakti Bhawan Extn.
Lucknow-226001
Telephone No.- 0522-2287030/ 2288056
CIN :U40101UP1980SGC005065
E-mail: gm.commercial@uprvunl.org

पत्रांक - 186/उनिलि/मु0अभि0(वाणिज्य)/एल0एम0वी0-10

दिनांक : 22, मार्च, 2019

अधिसासी निदेशक (वित्त)
उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
8 वॉ तल, शक्ति भवन विस्तार,
लखनऊ।

मुख्य अभियन्ता (परियोजना समन्वयक)
उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
अनपरा, ओबरा, पारीछा, हरदुआगंज, पनकी, जवाहरपुर
सोनभद्र, झॉसी, अलीगंज कानपुर, एटा।

**विषय : मा0 विद्युत नियामक आयोग के आदेश दिनांक 22.01.2019 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए घोषित विद्युत
रेट शिड्यूल लागू करने के सम्बन्ध में।**

कृपया अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 ने मा0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा दिनांक 22.01.2019 को घोषित वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु टैरिफ आदेश एवं अध्यक्ष (उ0प्र0पा0का0लि0) द्वारा जारी अधिसूचना सं0 44/एच0सी0/यूपीपीसीएल/पांच-1974-1204-सी/2019, दिनांक 30.01.2019 (संलग्न) को आदेश सं0 45/एच0सी0/ टैरिफ /2018-19, दिनांक 30.01.2019 (संलग्न) द्वारा लागू कर दिया है तथा विभिन्न समाचार पत्रों में सूचना दिनांक 26.01.2019 को प्रकाशित हो चुकी है। पुनरीक्षित दरें दिनांक 02.02.2019 से प्रभावी होंगी।

यह भी अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 ने अपने कार्यालय ज्ञापन सं0 66/मु0अ0(वा0 एवं ऊ0ले0)/वा0-1/एलएमवी-10(2018-19), दिनांक 15.02.2019 (संलग्न) द्वारा समस्त सेवारत/सेवानिवृत्त विद्युत कार्मिकों अथवा उनके स्पाउस के लिए एल0एम0वी0-10 श्रेणी में विद्युत उपभोग की सुविधा पूर्व में जारी कार्यालय ज्ञापन सं0 58/ मु0अभि0/ वा0-1/एलएमवी-10(2017-18), दिनांक 07.02.2018 (संलग्न) के प्रावधानों को आगामी आदेशों तक यथावत् रखा है।

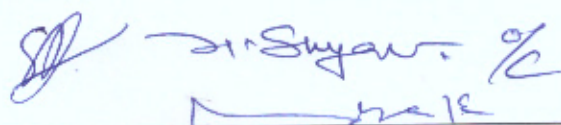
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा जारी उपरोक्त समस्त आदेश, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0 के निदेशक मण्डल की दिनांक 07.01.2019 को सम्पन्न हुई 179वीं बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार इस कार्यालय द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन सं0 84/उनिलि/मु0अभि0(वाणिज्य)/एल0एम0वी0-10, दिनांक 01, फरवरी, 2019 तथा Electricity Act-2003 के The Electricity (Removal of difficulty) Fourth Order, 2005 के अनुपालन में उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के समस्त सेवारत/सेवानिवृत्त विद्युत कार्मिकों अथवा उनके स्पाउस के विभिन्न श्रेणियों हेतु तथा परियोजना कालोनी में अवस्थित अन्य उपभोक्ताओं के लिए भी दिनांक 02.02.2019 से लागू की जाती हैं।

कृपया तदनुसार सेवारत कार्मिकों के वेतन से प्रति माह विद्युत शुल्क की कटौती सुनिश्चित करने का कष्ट करें तथा सेवानिवृत्त कार्मिकों अथवा उनके स्पाउस एवं अन्य उपभोक्ताओं से विद्युत शुल्क नियमानुसार जमा करने का कष्ट करें।

ऐसे सेवानिवृत्त कार्मिक अथवा उनके स्पाउस जो विद्युत शुल्क सीधे उ0प्र0पा0का0लि0/सम्बन्धित डिस्काम में जमा करना चाहते हैं, वह सम्बन्धित वितरण खण्डों में भी अपने निर्धारित विद्युत शुल्क अपनी संयोजन संख्या के विरुद्ध जमा कर सकते हैं।

सम्बन्धित वितरण निगम के परिक्षेत्र में लागू रेगुलेटरी सरचार्ज मा0 नियामक आयोग के आदेश के अनुसार देय होगा।

संलग्नक:-यथोपरोक्त।



(रमेश चन्द्र)

मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)

**COMMERCIAL
UNIT**



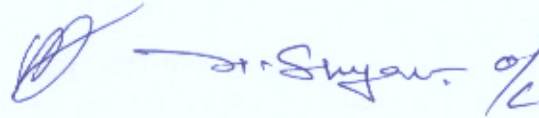
U.P. Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd.
14th floor, Shakti Bhawan Extn.
Lucknow-226001
Telephone No.- 0522-2287030/ 2288056
CIN :U40101UP1980SGC005065
E-mail: gm.commercial@uprvunl.org

पत्रांक - 186/उनिलि/मु0अभि0(वाणिज्य)/एल0एम0वी0-10

दिनांक : 22 , मार्च , 2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, 7 वॉ तल, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0, 7 वॉ तल, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल/पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/आगरा/लखनऊ/मेरठ/केसको, कानपुर।
4. निदेशक (परि0 एवं वा0/तकनीकी/वित्त/कार्मिक) उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, 8 वॉ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. निदेशक (वाणिज्य), उ0प्र0पा0का0लि0, 6 वॉ तल, शक्ति भवन, लखनऊ।



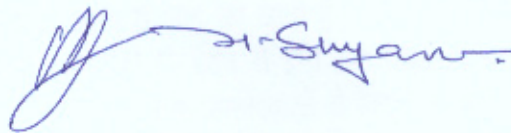
(रमेश चन्द्र)
मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)

पत्रांक - 186/उनिलि/मु0अभि0(वाणिज्य)/एल0एम0वी0-10

दिनांक : 22 , मार्च , 2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

6. मुख्य अभियन्ता (तापीय परिचालन/ईंधन/आर0 एण्ड एम0/पी0पी0एम0एम0/पर्या0 एवं सुरक्षा/जानपद- नव परि0/ मानक संसाधन/प्रगति), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति), विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि इस पत्र को संलग्नकों सहित उत्पादन निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने की व्यवस्था करें।
8. अधिशासी अभियन्ता, समस्त विद्युत वितरण खण्ड (उ0प्र0पा0का0लि0/समस्त डिस्काम)।
9. मुख्य प्रबन्धक (कैश प्रबन्धन इकाई), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, 7 वॉ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. उपमुख्य लेखाधिकारी, समस्त परियोजनायें, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0।



(रमेश चन्द्र)
मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०
"वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा"
चतुर्थ तल, शक्ति भवन विस्तार,
14-अशोक मार्ग, लखनऊ।
दूरभाष : 0522-2287868, फैक्स : 0522-2287834
ई-मेल : cecomuppl@gmail.com
CIN NO:- U32201UP1999SGC024928



पत्रांक:- /एच०सी०/टैरिफ/2018-19

दिनांक/जनवरी, 2019

विषय :- मा० विद्युत नियामक आयोग के आदेश दिनांक 22.01.2019 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए घोषित रेट शिड्यूल लागू करने के सम्बन्ध में।

ई-मेल/
स्पीड पोस्ट

प्रबन्ध निदेशक
पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पूर्वांचल
विद्युत वितरण निगम लि०
मेरठ/लखनऊ/आगरा/वाराणसी।

No. 250 Dir. (Proj. & Com.)/UNL
Date 05/02/19

प्रबन्ध निदेशक
केस्को
कानपुर।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि मा० विद्युत नियामक आयोग द्वारा दिनांक 22.01.2019 को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए टैरिफ आदेश निर्गत कर दिया गया है। टैरिफ आदेश के अन्तर्गत निर्गत रेट शिड्यूल को लागू करने के लिए विभिन्न समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना दिनांक 26.01.2019 को प्रकाशित हो चुकी है। पुनरीक्षित दरें दिनांक 02.02.2019 से प्रभावी होंगी।

उक्त के तारतम्य में उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा निर्गत अधिसूचना सं० 44/एच०सी०/यूपीपीसीएल/पांच-1974-1204-सी/2019 दिनांक 30.01.2019 की प्रति संलग्नकों सहित आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया अपने स्तर से अपने डिस्काम के अधीन समस्त अधिकारियों को इसे उपलब्ध कराते हुए पुनरीक्षित दरों को लागू किये जाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने की कृपा करें। इसके अतिरिक्त नये रेट शिड्यूल के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु बिलिंग साफ्टवेयर में ससमय आवश्यक परिवर्तन करवाना भी अपने स्तर से सुनिश्चित करने की कृपा करें। अधिसूचना की प्रतिलिपि ई-मेल द्वारा भी आपको प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक :- यथोपरि।

Commercial Unit
U.P. Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd
Dy. No. 102 Date 05/2/19

भवदीय,

(ए०के० पाठक)

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा

No. 299
Dated 02.2.19

प्रबन्ध निदेशक
उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०

संख्या : 115/एच०सी०/टैरिफ/2018-19/तददिनांक : 30-1-2019

प्रतिलिपि संलग्नकों सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, उ०प्र० विद्युत नियामक आयोग, विद्युत नियामक भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
2. अध्यक्ष महोदय के निजी सहायक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
3. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. समस्त निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

संलग्नक : यथोपरि।

Er SK Yadavae
Er S. Agrawal AE
06.02.19
EE

CF (Comm.)
परियोजना एवं वाणिज्य

(ए०के० पाठक)

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा



U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(U.P. GOVT. UNDERTAKING)
SHAKTI BHAWAN, 14-ASHOK MARG
LUCKNOW



No. 44 /H.C./UPPCL/V-1974-1204-C/2019

Dated : January 30, 2019

NOTIFICATION

In conformity of tariff order dated 22.01.2019 issued by U.P. Electricity Regulatory Commission in exercise of powers under section 24 of the Electricity Reforms Act, 1999 and section 61 and 62 of Electricity Act-2003 and all other power in this behalf and in supersession of all previous notifications, orders and instructions on the subject, U.P. Power Corporation Ltd. hereby notify that:-

1. (A) The rate schedules and schedule of miscellaneous charges appended hereto, shall apply to all consumers in respect of supply of electricity throughout the area of supply of all Government owned distribution companies in the state of Uttar Pradesh.
- (B) (i) **Regulatory Surcharge-2 @ 4.28%** shall be levied on the consumers in the supply area of DVVNL, MVVNL, PuVVNL and @ 0.00% in supply area of PVVNL.
- (ii) **For KESCO, Regulatory Surcharge-2 @ 4.13%** (for all categories except LMV-1 & LMV-5) shall be applicable. Consumer of category LMV-1 & LMV-5 shall be levied **Regulatory Surcharge-2 @ 3.91%**.

Note: Regulatory surcharge applicable till further issuance of order by the Commission.

- (C) The rates/charges as specified in 1 (A) and (B) above shall come into force w.e.f. **02.02.2019.**
2. The rate schedules shall, besides, be subject to levy of such charges or surcharges and electricity duty as may be imposed by the Government and/or UPERC from time to time.
3. In addition to condition mentioned in para-2 above, the rates of charge, conditions of supply and other matters specified in the schedules annexed hereto, shall replace the existing rates of charge and corresponding provisions in the existing rate schedules and in the existing agreements, if any, with the erstwhile UPSEB/U.P. Power Corporation Ltd/all Government owned distribution companies, w.e.f. **02.02.2019.**

Annexure : As above

By Order,

(Alok Kumar)

Chairman

UPPCL, MVVNL, DVVNL, PVVNL, PuVVNL, KESCO

RATE SCHEDULE LMV – 1:

DOMESTIC LIGHT, FAN & POWER:

1. APPLICABILITY:

This schedule shall apply to:

- a) Premises for residential / domestic purpose, Accommodation for Paying Guests for Domestic purpose (Excluding Guest Houses), Janata Service Connections, Kutir Jyoti Connections, Jhuggi / Hutments, Places of Worship (e.g. Temples, Mosques, Gurudwaras, Churches) and Electric Crematoria, Shelter Homes, orphanages, old age homes, Institutions run for mentally retarded and forsaken children. **Non-commercial places occupied by religious persons, of any religion, are also entitled in this category, for a maximum load up to 5 kW, subject to the condition that such non-commercial place shall have a valid registration/recognition from a charitable trust.**

b) Mixed Loads

i. 50 kW and above

- a. Registered Societies, Residential Colonies / Townships, Residential Multi-Storied Buildings with mixed loads (getting supply at single point) with the condition that at least 70% of the total contracted load shall be exclusively for the purposes of domestic light, fan and power. The above mixed load, within 70%, shall also include the load required for lifts, water pumps and common lighting,
- b. Military Engineer Service (MES) for Defence Establishments (Mixed load without any load restriction).

ii. Less than 50 kW

Except for the case as specified in Regulation 3.3 (e) of Electricity Supply Code, 2005 as amended from time to time, if any portion of the load is utilized for conduct of business for non-domestic purposes then the entire energy consumed shall be charged under the rate schedule of higher charge

2. CHARACTER AND POINT OF SUPPLY:

As per the applicable provisions of Electricity Supply Code, 2005 and its amendments.

3. RATE:

Rate, gives the fixed and energy charges at which the consumer shall be billed during the billing period applicable to the category:

(a) Consumers getting supply as per 'Rural Schedule':

Description	Description	Fixed charge	Energy charge)
i) Un-metered	All Load	Rs. 400 / kW / month	Nil

Description	Consumption Range	Fixed* Charge	Energy Charge
ii) Metered	For first 100 kWh / month*	Rs. 80.00 / kW / month	Rs. 3.00 / kWh
	For next 101 - 150 kWh / month		Rs. 3.50 / kWh
	For next 151 – 300 kWh / month		Rs. 4.50 / kWh
	For next 301 – 500 kWh / month		Rs. 5.00 / kWh
	For above 500 kWh / month (Starting from 501 st unit)		Rs. 5.50 / kWh

*For consumers with contracted load up to 1 KW and not consuming more than 100 units per month, fixed charges shall be Rs. 50.00 / kW / month

(b) Supply at Single Point for bulk loads (50 kW and above, Supplied at any Voltage):

Description	Fixed Charge	Energy Charge
For Townships, Registered Societies, Residential Colonies, multi-storied residential complexes (including lifts, water pumps and common lighting within the premises) with loads 50 kW and above with the restriction that at least 70% of the total contracted load is meant exclusively for the domestic light, fan and power purposes and for Military Engineer Service (MES) for Defence Establishments (Mixed load without any load restriction).	Rs. 95.00 / kW / Month	Rs. 6.10 / kWh

The body seeking the supply at Single point for bulk loads under this category shall be considered as a deemed franchisee of the Licensee. Such body shall charge not more than 5% additional charge on the above specified 'Rate' from its consumers apart from other applicable charges such as Regulatory Surcharge, Penalty, Rebate and Electricity Duty on actual basis.

The 5% additional charge shall be towards facilitating supply of electricity to the individual members to recover its expenses towards supply of electricity, distribution loss, electrical maintenance in its supply area, billing, accounting and audit etc.

The deemed franchisee is required to provide to all its consumers and the licensee, a copy of the detailed computation of the details of the amounts realized from all the individual consumers and the amount paid to the licensee for every billing cycle on half yearly basis. If he fails to do so, then the consumers may approach the Consumer Grievance Redressal Forum (CGRF) having jurisdiction over their local area for the redressal of their grievances.

The deemed franchisee shall arrange to get its account(s) audited by a Chartered Accountant mandatorily. The audited accounts will be made available to all the consumers of the deemed franchisee within 3 months of the closure of that financial year. If he fails to do so, then the consumers may approach the Consumer Grievance Redressal Forum (CGRF) having jurisdiction over their local area for the redressal of their grievances.

The deemed franchisee should separately meter the electricity supplied from back up arrangements like DG sets etc. The bill of its consumers should clearly depict the units and rate of electricity supplied through back up arrangement and electricity supplied through Licensee.

The deemed franchisee shall not disconnect the supply of electricity of its consumers on the pretext of defaults in payments related to other charges except for the electricity dues regarding the electricity consumed by its consumers and electricity charges for lift, water lifting pump, streetlight if any, corridor / campus lighting and other common facilities.

In case the deemed franchisee exceeds the contracted load / demand under the provisions of Clause 7(ii) – 'Charges for Exceeding Contracted demand' of the General Provisions of this Rate Schedule, only in such case the deemed franchisee will recover the same from the individual members who were responsible for it on the basis of their individual excess demands.

(c) OTHER METERED DOMESTIC CONSUMERS:

1. **Lifeline consumers:** Consumers with contracted load of 1 kW, energy consumption up to 100 kWh / month.

Description	Fixed Charge	Energy Charge
Loads up to 1 kW only and for consumption up to 100 kWh / month	Rs. 50.00 / kW / month	Rs. 3.00 / kWh

2. **Others:** Other than Lifeline consumers (i.e. consumers who do not qualify under the criteria laid above for lifeline consumers.)

Description	Consumption Range	Fixed Charge	Energy Charge
All loads	For first 150 kWh / month	Rs. 100.00 / kW / month	Rs. 4.90 / kWh
	For next 151 - 300 kWh / month		Rs. 5.40 / kWh
	For next 301 – 500 kWh / month		Rs. 6.20 / kWh
	For above 500 kWh / month (Starting from 501 st unit)		Rs. 6.50 / kWh

Note:

For all consumers under this category the maximum demand during the month recorded by the meter has to be essentially indicated in their monthly bills. However, this condition would be mandatory only in case meter reading is done by the Licensee. Accordingly, if the bill is being prepared on the basis of reading being submitted by the consumer then the consumer would not be liable to furnish maximum demand during the month and his bill would not be held back for lack of data of maximum demand.

RATE SCHEDULE LMV- 10:

DEPARTMENTAL EMPLOYEES AND PENSIONERS:

1. APPLICABILITY:

This schedule shall apply only to such employees (including the cases of retired / voluntary retired or deemed retired) of Licensees / successor entities of erstwhile Uttar Pradesh State Electricity Board (UPSEB), who own electricity connection in their own name and opt for the same for their own use for light, fan and power for domestic appliances, where the energy is being fed directly from Licensee mains. The Schedule shall also apply to spouse of employees served under Licensees / successor entities of erstwhile UPSEB.

2. RATE:

For all such consumers LMV-1 rate schedule will be applicable. However, the Licensees are authorised to provide "rebate" as they deem fit to the consumers eligible to get supply under this category.

3. ELECTRICITY DUTY:

Electricity duty on the above shall be levied in addition at the rates as may be notified by the State Government from time to time.

4. OTHER PROVISIONS:

- (i) For serving / retired employees and their spouse, the supply will only be given at one place where Licensee's mains exist. The electric supply under this tariff will be given only at one place, within the area of erstwhile UPSEB / its successor companies.
- (ii) Concerned executive engineers will take an affidavit from all employees and pensioners that the electricity supplied to their premises is being used exclusively for the purpose of domestic consumption of themselves and their dependants. It will have to be certified by the employees/pensioners that such electricity is not being used for any other purpose or to any individual to whom his house has been rented out. Without any prejudice to any legal action as provided in the legal framework, any misuse to above effect shall invalidate him from the facility of LMV-10 on permanent basis.
- (iii) In the event of transfer of the employee, this tariff shall be applied at the new place of posting only when a certificate has been obtained from the

concerned Executive Engineer of the previous place of posting, that the supply under this tariff has been withdrawn at previous place of posting. Further, the employee shall also be required to submit an affidavit that he is not availing the benefit of LMV-10 connection anywhere else in the state.

- (iv) Those who are not availing this tariff shall also give a declaration to this effect. This declaration shall be pasted / kept in his service book / personal file / Pensioners record. If the declaration is found wrong, necessary action against the employee shall be taken as per the provisions of service rules. If declaration has already been given at the present place of posting then further declaration is not necessary due to this revision. Pensioners shall also have to give a similar declaration for availing departmental tariff at only one place. In case this declaration is found wrong, this tariff shall be withdrawn forever.
- (v) No other concession shall be admissible on this tariff.
- (vi) The schedule of miscellaneous charges as appended with Licensee's General Tariff as amended from time to time and Electricity Supply (Consumers) Regulation, 1984 as enforced from time to time shall also be applicable on the employee / pensioner receiving supply under this schedule.
- (vii) Retired employees drawing pension from the Treasury / Bank will have to pay the monthly electricity charges as per the rates given in the rate schedule applicable to their category.

अपर्णा यू०
आई०ए०एस०
प्रबन्ध निदेशक



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन

(उत्तर प्रदेश सरकार)
शक्ति भवन, 14- अशोक मार्ग,
ई-मेल : mduppc112@upcl
दूरभाष - (0522) 22
फैक्स - (0522) 2200910

CIN NO:- U32201UP1999SGC024928



पत्रांक:- /मु०अ०(वा० एवं ऊ०ले०)/वा०-1/LMV-10(2018-19)

दिनांक/फरवरी, 15 2019

कार्यालय ज्ञाप

एतद् द्वारा मा० विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ आदेश दिनांक 22.01.2019 में समस्त विद्युत उपभोक्ता श्रेणियों की पूर्व की दरों के सापेक्ष दरों में कोई परिवर्तन नहीं किये जाने के आलोक में विभागीय/सेवारत/सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों/पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों हेतु एल०एम०वी०-10 श्रेणी में विद्युत उपभोग की सुविधा हेतु पूर्व के जारी कार्यालय ज्ञाप सं० 58/मु०अभि०/वा०-1/LMV-10(2017-18) दिनांक 07.02.2018 के प्रावधानों को आगामी आदेशों तक यथावत् रखा जाता है।

EE (Comm)

EE (Comm)

अपर्णा यू०

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक:- 66 /मु०अ०(वा० एवं ऊ०ले०)/वा०-1/LMV-10(2018-19)/तददिनांक: 15-2-2019

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1. निजी सचिव, अध्यक्ष महोदय, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
 2. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
 3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
 4. निदेशक (का० प्रब० एवं प्रशा०)/निदेशक (वित्त)/निदेशक (वाणिज्य)/निदेशक (वितरण)/निदेशक (कारपोरेट प्लानिंग) उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
 5. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/आगरा/लखनऊ/मेरठ एवं केरको-कानपुर।
 6. निदेशक (वाणिज्य), पूर्वांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/आगरा/लखनऊ/मेरठ एवं केरको-कानपुर।
 7. मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
 8. समस्त मुख्य अभियन्ता, उ०प्र०पा०का०लि० मुख्यालय, लखनऊ।
 9. मुख्य अभियन्ता (आर०ए०यू०), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
 10. मुख्य लेखाधिकारी (केन्द्रीय भुगतान प्रकोष्ठ), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
 11. अधीक्षण अभियन्ता (आई०टी०), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
 12. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को कारपोरेशन की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

अपर्णा यू०
प्रबन्ध निदेशक



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०
"वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा"
चतुर्थ तल, शक्ति भवन विस्तार,
14-अशोक मार्ग, लखनऊ।
दूरभाष : 0522-2287868, फ़ैक्स : 0522-2287834
ई-मेल : cecomuppcl@gmail.com
CIN NO:- U32201UP1999SGC024928

पत्रांक:- 58 / मु०अभि०/वा०-1/LMV-10/(2017-18)

दिनांक/फरवरी, 7 2018

कार्यालय ज्ञाप

वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु विभागीय सेवारत/सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों हेतु एल०एम०वी०-10 श्रेणी में विद्युत उपभोग की सुविधा निम्नवत् अनुमन्य की जाती है:-

Category	Fixed Charge/month (Rs.)	Fixed Monthly Energy Charge (Rs.)
Class IV employees/Operating staff	175.00	195.00
Class III employees	205.00	245.00
JE & equivalent posts	280.00	460.00
AE & equivalent posts	305.00	605.00
EE & equivalent posts	325.00	645.00
SE/D.G.M. & equivalent posts	595.00	760.00
CE (I&II)/General Manager and above	650.00	880.00
Additional charge for using A.C. (April to Sep.)	Rs. 650.00 per month per AC	

एल०एम०वी०-10 श्रेणी के उपभोक्ताओं के संयोजनों पर मीटर लगने की स्थिति में अनमीटर्ड संयोजन हेतु निर्धारित दरों के अनुसार रेट चार्ज का 20 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी, तथा विद्युत कर 20 प्रतिशत (अनमीटर्ड संयोजन पर) के स्थान पर रेट चार्ज का 5 प्रतिशत देय होगा। अन्यथा अनमीटर्ड संयोजन पर विद्युत कर रेट चार्ज का 20 प्रतिशत देय होगा।

एल०एम०वी०-10 श्रेणी पर लागू उपरोक्तानुसार व्यवस्था की प्रभावी तिथि अन्य श्रेणियों की प्रभावी तिथि अर्थात् 09.12.2017 के समान ही होगी।

आज्ञा से
निदेशक मण्डल
उ०प्र० पा०का०लि०

(संबंधित वितरण निगम में लागू रेगुलेटरी सरचार्ज मा० नियामक आयोग के आदेश के अनुसार देय होगा)।

संख्या: 58 -मु०अभि०/वा०-1/LMV-10/(2017-18) तददिनांक 7-2-2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष महोदय उ०प्र० पा०का०लि०, लखनऊ।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश, पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
4. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)/निदेशक (वित्त)/निदेशक (वाणिज्य)/निदेशक (वितरण)/निदेशक (कारपोरेट प्लानिंग) उ०प्र० पा०का०लि०, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल/पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/आगरा/लखनऊ/मेरठ, केस्को, कानपुर।
6. निदेशक (वाणिज्य) पूर्वांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल/पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/आगरा/लखनऊ/मेरठ, केस्को, कानपुर।
7. मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त) उ०प्र० पा०का०लि०, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता (आर०ए०यू०) उ०प्र० पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. मुख्य लेखाधिकारी (केन्द्रीय भुगतान प्रकोष्ठ) उ०प्र० पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. अधिशासी अभियन्ता (वेब) उ०प्र० पावर कारपोरेशन को आदेश को कारपोरेशन की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(ए०के० पाठक)
मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा

प्रति निदेशक (वाणिज्य) उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०,
14 वीं तल शक्ति भवन विस्तार लखनऊ को सूचना एवं
आवश्यक कार्यवाही हेतु उचित।

(5/02/18)
J. (Gm) JPPCL

(1)

THE ELECTRICITY (REMOVAL OF DIFFICULTY) FOURTH ORDER, 2005*

Whereas the provisions of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) (hereinafter referred to as the Act), came into force on the 10th June, 2003;

And whereas "generating station" has been defined in sub-section (30) of section 2 of the Act as any station for generating electricity, including any building and plant with step-up transformer, switch yard, switch-gear, cables or other appurtenant equipment, if any used for that purpose and the site thereof, a site intended to be used for a generating station, and any building used for housing the operating staff of a generating station, and where electricity is generated by water-power, includes penstocks, head and tail works, main and regulating reservoirs, dams and other hydraulic works, but does not in any case include any sub-station;

And whereas no licence is required for a generating company to establish, operate and maintain a generating station as per the provisions of the section 7 of the Act;

And whereas providing the housing to the operating staff of a generating station in the vicinity of the generating station is essential for operation and maintenance of the generating station and forms an integral part of the generating station;

And whereas difficulties have arisen regarding the requirement of licence for supplying power to the housing colonies or township housing the operating staff of the generating stations by the generating companies;

Now, therefore, the Central Government in exercise of its powers conferred by section 183 of the Act, hereby makes this order in respect of supply of electricity by the generating companies to the housing colonies of its operating staff, not inconsistent with the provisions of the Act, to remove difficulties, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) This order may be called The ELECTRICITY (REMOVAL OF DIFFICULTY) FOURTH ORDER, 2005.

(2) This order shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Supply of electricity by the generating companies to the housing colonies of its operating staff.—The supply of electricity by a generating company to the housing colonies of, or township housing, the operating staff of its generating station will be deemed to be an integral part of its activity of generating electricity and the generating company shall not be required to obtain licence under this Act for such supply of electricity.

*Vide S.O. 793(E), dated 8-6-2005, published in the Gazette of India, Ext., Pt. II, S. 3(ii), dated 8-6-2005.